

# दैनिक घटती घटना

Www.ghatatighatana.com

Ghatatighatana11@gmail.com

अमियकापुर, ग्रन्ड 20, अंक -295 मंगलवार, 27 अगस्त 2024, पृष्ठ - 8+8 मूल्य 4 रुपये -



## छत्तीसगढ़ सरकार 36 घंटे भी नहीं दिए

और उजाड़ दिया आशियाना  
अब तो बताईए मुख्यमंत्री जी... क्या छापे?

कलम बंद का  
पर इंकलाब होता रहेगा इंसाफतक... 56 वाँ दिन

क्या प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के लिए पूरे प्रदेश के लोगों से ऊपर उनके भतीजे हैं ?

» छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार क्या गैर संवेदनशील सरकार है...?

» सरकार को कमियां ना दिखाएं तो क्या दिखाएं...?

» क्या विष्णुदेव साय सरकार बेहतर चल रही है... सिर्फ यह बात आईएएस लॉबी को पता है... आम जनता को नहीं है जानकारी...?

» किसी का दिव्यांग प्रमाण-पत्र फर्जी वह करता है मंत्री के घर मनमर्जी, दिव्यांग मांग रहे अधिकार क्या उन्हे दोगे न्याय प्रदेश के कर्णधार?

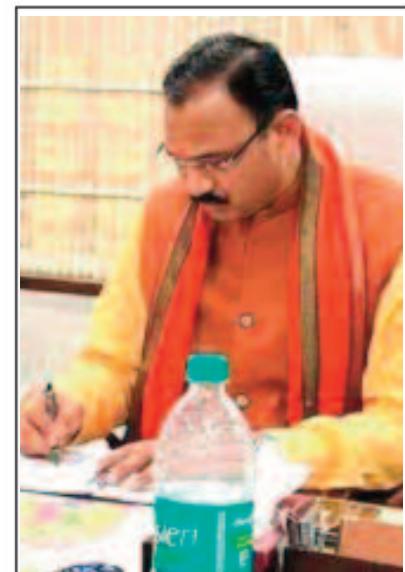
» क्या फर्जी दिव्यांग और फर्जी डिग्री के आधार पर जो कर रहे नौकरी उन्हे होगी जेल... उन्हें मिल सकेगा संकल्प पत्र अनुसार दण्ड...?

स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकारों को संरक्षण देने की बात कही... वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर जनसंपर्क अधिकारी को आगे कर समाचार-पत्र पर दबाव बनाने का कर रहे वह काम... ये कैसा संरक्षण?

कैसे पत्रकारों को मिलेगी सुरक्षा... कैसे समाचार-पत्र रह सकेंगे निष्पक्ष...

जब उन्हे सच लिखने पर मिलेगी सजा?

### तुगलकी फरमान के विरुद्ध कलमबंद अभियान...



छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के विभाग जनसंपर्क के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री

**श्री श्यामबिहारी जायसवाल** के विभाग से संबंधित समाचारों के प्रकाशन पर जनसंपर्क संचनालय के आयुक्त सह संचालक आईपीएस  
**श्री मयंक श्रीवास्तव**



के मौखिक आदेश पर घटती-घटना के शासकीय विज्ञापन पर रोक लगाकर दबाव बनाने से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के मूलभूत हक पर कुठाराधात के विरुद्ध कलमबंद अभियान... प्रशासनिक अत्याचार झेलने के बावजूद है जारी ...

घटती-घटना के स्लेही पाठकों, विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...

संपादक :- अविनाश कुमार सिंह

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महामहिम श्री रेमन डेका से हस्तक्षेप की मांग...

क्या छापें आयुक्त सहसंचालक आईपीएस मयंक श्रीवास्तव साहब?

स्पष्ट कीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी, स्पष्ट कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन, स्पष्ट कीजिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन... गृहमंत्री जी, भारत सरकार क्या छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को लेकर खबर प्रकाशन पर होगी समाचार पत्र पर कार्यवाही ?





-भूपेन्द्र सिंह-  
अम्बिकापुर/रायपुर 26 अगस्त  
2024 (घटती-घटना)।

नियमों को तोड़ - मरोड़ कर जो कार्यवाही की वह किसी से छुपी नहीं है, यहां तक कि भू-राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत, अगर किसी व्यक्ति या संस्था पर सरकारी जमीन पर कब्ज़े या अतिक्रमण का शक हो, तो उसे नोटिस भेजा जाता है, नोटिस जारी होने के बाद, मामले को तहसीलदार की अदालत में दर्ज कर लिया जाता है, कम से कम एक बार सुनवाई के बाद अगर प्रशासन यह साबित कर पाता है कि संबंधित व्यक्ति ने सरकारी जमीन घेरी है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है, संशोधित नियमों के मुताबिक, यह जुर्माना घेरी गई जमीन के बाज़ार मूल्य का 20 प्रतिशत तक हो सकता है, अगर जारी नहीं जाता तो इसे जमीन से ना

जुमाना नहीं जमा किया जाता, तो उस व्यक्ति को जेल भी भेजा जा सकता है... वहीं दंड सहिता की धारा 166 के अनुसार, सरकारी कर्मचारी जो दूसरे को चोट पहुंचाने के इरादे से कानून का उल्लंघन करता है, उसे कारावास या जुर्माना या दोनों की अवधि के साथ दंडित किया जा सकता है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी आपको नुकसान पहुंचता है या अपमान करता है, तो आईपीसी का यह प्रावधान लागू हो सकता है पर सरगुजा कलेक्टर कितने बेबस थे...मंत्रियों के समन...की...उन्होंने कानूनी प्रावधानों को भी ध्यान नहीं दिया और वहीं किया जो ऊपर से मंत्री ने उहें आदेश दिया।

मंत्री जो कौन सा जन्मघृष्टा  
पिला दिये थे की सब आदेश  
एक दिन में तैयार हो गया,  
इसके पीछे राज तथा है

सरगुजा कलेक्टर विलास थोसकर संदीपान आखिर आप क्यों कानून के नियमों को तोड़-मरोड़ कर रखने को मजबूर हो गये...मंत्री जी कौन सा जादुई कलम दिये थे...कि सब आदेश एक दिन तैयार हो गया था...?

तत्काल तो हिम्मत दिखा  
दिये...बस ये हिम्मत  
कि

**जमीन कीमती तब हो गई जब दैनिक घटती-घटना ने अपना कलम बंद कर दिया...**

कई कलेक्टर आए गए भाजपा से लेकर कांग्रेस तक की सरकार आई उनके शासन में भी कलेक्टर आए व गए किसी को भी वह जमीन कीमती नहीं लगी, जमीन कीमती तब हो गई जब दैनिक घटती-घटना ने अपना कलम बंद कर दिया। ऐसे में सवाल तो यही उत्ता है कार्यावाही तो सिर्फ एक बहाना था यहां तो दैनिक घटती-घटना अखबार के कलम अब कलेक्टर सरगुजा के लिए भी एक खुला-पत्र समाचार-पत्र की तरफ से प्रेषित है कि उन्होंने एक मंत्री के विवादित फर्जी डिग्री वाले भतीजे के लिए कानून को ही ताक पर रख दिया क्योंकि मंत्री का विवादित फर्जी डिग्री वाला भतीजा ऐसा चाहता था और ऐसा नहीं होने पर उसकी नौकरी चली जाती। कलेक्टर सरगुजा ने तत्काल तो हिम्मत दिखा दी... समाचार-पत्र कार्यालय/प्रतिष्ठान उन्होंने जमींदेज कर दिया लेकिन अब वह अंत तक हिम्मत

रना था। एक  
न से टक्कर  
यह बताना था,  
प्रशासन प्रशासन  
लेना नहीं तो  
ग कार्यवाही के  
छ और महीने  
कलेक्टर बने  
ग कार्यवाही की है  
उपहार से कम  
ग पुस्तक होना  
ल उठता है की  
पढ़ा-लिखा कर  
न व्यवस्था को  
ड़ दे।

सम्हाल कर रखें क्योंकि अब न्याय की  
लड़ाई अंजाम तक जायेगी और हर बात  
का जवाब कानूनी प्रक्रिया अनुसार  
लिया जायेगा की कानून का पालन क्यों  
नहीं किया गया वहीं दो विवादित फर्जी  
लोगों के लिए पूरे प्रदेश की सरकार  
साथ ही सर्वज्ञ जिला प्रशासन इन  
आत्मीयता से भर गया की उनके लिए  
कानून ही ताक पर रख दिया। वैसे सवाल  
यह भी है की क्या हर फर्जी डिगी वाले साथ  
ही फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र वाले अधिकारी  
कर्मचारी के साथ यहीं नियम लागू होगा इस  
सरकार के कार्यकाल में... क्या असल की  
जगह फर्जी वाला ही नौकरी में होगा असल  
आंदेलन ही करता रहेगा।

**जनमध्यटी  
ब आदेश  
हो गया,  
वया है**

भास भोसकर  
यों कानून के  
कर रखने को  
कौन सा जादुई  
आदेश एक

**त दिखा  
हमत  
गणा...  
लिए भी एक  
की तरफ से**

**कलेक्टर साहब...अब  
आप ही पूछ कर बता  
दीजिए...कि क्या छापे ?**

कलेक्टर सरगुजा से एक आग्रह भी है  
समाचार-पत्र का की अब वह ही पूछकर  
बता दें की क्या छापे। समाचार-पत्र ने  
कलम बंद किया तो पूरी सरकार दहल  
गई समाचार पत्र को बंद करने उसके  
विरोध को दबाने बुलडोजर तक चल  
दिया गया लेकिन फिर भी सरकार ने यह  
नहीं बताया की क्या छापे...समाचार-पत्र  
में...चूकि दैनिक घटती-घटना समाचार  
पत्र के विरोध को कुचलने का जिम्मा  
कलेक्टर सरगुजा का था ऐसे में उनके  
माध्यम से ही अब सवाल है की वहीं  
सरकार से यह पूछकर समाचार-पत्र के  
अवगत करा दें की क्या छापे।

खुला पत्र प्रधानमंत्री को...  
प्रधानमंत्री जी...हमारा अपराध बस्ति इतना है की विवादित प्रमाण-पत्र से नियुक्त ओएसडी संजय मरकाम व नियम विरुद्ध तरीके से बने प्रभारी डीपीएम प्रिंसिपल जायसवाल के मामले की जांच का समाचार हम अखबार में प्रकाशित कर रहे थे...और यह मांग हम नहीं पूछ सरकार से लेकर वर्तमान सरकार तक के

सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर संदीपान  
आखिर आप क्यों कानून के नियमों को तोड़-  
मरोड़ कर प्रस्तुत करने को मजबूर हो गये ?

दैनिक घटती-घटना कार्यालय साथ ही संपादक के प्रतिष्ठान को कलेक्टर सरगुजा ने अल सुबह जमीदोज कर दिया जो 28 जुलाई की सुबह थी, संपादक को कानून के अनुसार न समय दिया गया पर्यास न ही इस कार्यवाही के दौरान यह भी ध्यान रखा गया की बरसात के दिन में बेंदखली की कार्यवाही नहीं की जाती है वहीं यह भी ध्यान नहीं रखा गया की जिसके विरुद्ध कार्यवाही हो रही है उसके पिता का देहांत हुआ है और अभी हिन्दू रीति रिवाज अनुसार उसके यहां दशकर्म का भी कार्यक्रम नहीं संपन्न हुआ है ऐसे में वह कैसे बेंदखली के खिलाफ कहीं दौड़भाग कर सकेगा, कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो कलेक्टर सरगुजा की पूरी कार्यवाही ऐसी नजर आई जिसमें नियमों को इस्तिए तोड़ा-मरोड़ा गया जिससे दैनिक घटती-घटना समाचार पत्र कार्यालय साथ ही संपादक का प्रतिष्ठान जमीदोज किया जा सके। अब इस मामले में कलेक्टर सरगुजा से एक ही सवाल है की अखिर वह क्यों इतने मजबूर हो गए? किसके कहने पर वह एक समाचार पत्र की आवाज दबाने निकल पड़े और कौन उन्हे अपनी उंगलियों पर नचा ले गया? जिसके कारण वह न्याय के विपरीत जाकर दुर्भावना से काम कर गए। वैसे इस मामले में शिकायतकर्ता एक सविदा स्वास्थ्य अधिकारी था जिसकी डिग्री भी फर्जी है ऐसा आरोप है वहीं उसके ऊपर कोरोना महामारी के दौरान मरीजों को मिलने वाली निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं के भी बंदबांट का आरोप है वहीं आज भी वह लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं में से की कटौती कर अपनी सुविधा जुटाता है और वही है गिरफ्त में कर ले गया उन्हे गलत करने मजबूर कर ले गया वहीं सरकार और स्वास्थ्य था क्योंकि चाचा मंत्री हैं और तभी उसकी नौकरी बची है। और इसके पीछे का प्रकाशन जिससे आहत था वह और उसने ही रणनीति बनाई, जिस रणनीति पर चल मयं श्रीवास्तव भी मजबूर हुए कलेक्टर सरगुजा भी मजबूर हुए वहीं जिला प्रशासन



**मीडिया संस्थान के खिलाफ हुई कार्रवाई में अधोषित आपातकाल का संकेतः गुलाब**

डीपीएम साथ ही  
एसडी के प्रमाण पत्रों की  
ही प्रभारी डीपीएम के उन  
हो...जिला प्रशासन सरगुजा के द्वारा...।  
**वर्त्यों...जून 2024 से विज्ञापन**  
**उन्नीसवें संसदीय वर्ष**

की जांच जिनमें भ्रष्टाचार हैं से क्यों आपत्ति है? क्या गलत यह जांच के बाद तय ए। प्रधारी डीपीएम की डिग्री इसकी शिकायत की जांच हो रही है? ओएसडी फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर रखा रहा है? क्यों जांच नहीं हो पाया यह अधिकार खास लोगों यदि फर्जी डिग्री और फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी जायज अधिकार सभी को प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री जी...क्यों कोई रोड़ें खर्च करे मेहनत करे ही उसे पद मिलता है?

सच है...सच लिखना

बद...पूछन पर मत्रा जा का  
मौखिक शिकायत था मर्याद  
श्रीवास्तव साहब का उत्तर था ?

विरोध स्वरूप कलम बंद कर दिये और पूछे की आप ही बताओ कि क्या घपे...फिर क्या था...कर दिये अत्याचार और अविनाश सिंह घटनी-घटना के संपादक के संपत्ति को कुचल कर कानून का हवाला देने में कलेक्टर साहब पूरा कागजी व्यवस्था कर लिये...पर सुनवाई के अधिकार से वर्चित करने के लिये 5-6 जेसीबी...1 हाइड्रा...200-300 लोग भेज कर करवा दिये बुलडोजर कार्यवाही...जवाब और सवाल बहुत है...?

इन दोनों के प्रमाण-पत्र के जांच

**वयों माना जा रहा है?**  
एक विष्णु देव साय जी के स्वास्थ्य मंत्री ने व्यक्तिगत जांच ना हो ) कारणों से देकर सरगुजा में लोकतंत्र सरगुजा कलेक्टर विलास शास में लेकर गज्ज सासन बादे को सवालों के कठघरे दिया... सुनवाई के कानूनी वंचित करने के लिये कई ही था जो नहीं किया गया

**में आपति वयों...सरकार को?**  
प्रभारी डीपीएम व स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी के प्रमाण पत्र के जांच से आपति वयों है यदि आपति नहीं है तो तत्काल उन्हें हटाकर जांच वयों नहीं किया जा रहा? जांच कार्यवाही न होने को लेकर कई सवाल खड़े हैं कमियों को छापे वाले पत्रकार भी सरकार से टकरा रहे हैं और सरकार भी पत्रकारों पर अत्याचार करने को तैयार है पर जांच कार्यवाही में तपतरा वयों नहीं दिखाई जा रही यह भी एक सवाल है?

**घटती-घटना के स्थेही पाठकों, विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है..**

## खुला पत्र

देश के माननीय प्रधानमंत्री से भी सवाल... क्या भ्रष्टाचार के विरुद्ध  
छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार के खिलाफ समाचार लिखना है अपराध?

अम्बिकापुर, 26 अगस्त 2024 (घट्टी-घट्टा)। माननीय मुख्यमंत्री से भी सवाल है... छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है... केंद्र में भी आपकी पार्टी की सरकार है... पर छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमियां दिखाने से रोकने का भी प्रयास हो रहा है... यह प्रयास कहीं ना कहीं स्वस्थ लोकतंत्र को कमज़ोर करने का प्रयास है... जहां पर भाजपा सरकार से लोगों को बेहतर करने की उम्मीद होती है तो वहीं पर छत्तीसगढ़ में नवनिवाचित मंत्री, विधायक बे-लगाम हो चुके हैं... उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसे जिम्मेदारी को निभाने में असमर्थ दिख रहे हैं... उनकी कमियों को बताना उन्हें रास नहीं आ रहा इसलिए वह पत्रकार, संपादक का कलम बंद करने का प्रयास कर रहे हैं अब इस पर आप ही संज्ञान ले... और बताएं कौन सी खबर प्रकाशित करें?

## क्या छापें माननीय मुख्यमंत्री जी?



कलम  
बंद...

कलम  
बंद...का  
56 वां  
दिन



कलम  
बंद...का  
56 वां  
दिन



कलम  
बंद...

घट्टी-घट्टा के स्थेटी पाठकों, विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...

संपादक :- अविनाश कुमार सिंह

खुला पत्र

# भारत में सत्ये पत्रकार को राजनीतिक पार्टियों से खतरा क्यों रहता है?

अम्बिकापुर, 26 अगस्त 2024(घट्टी-घट्टा)। भारत अपने पत्रकारों को निडर होकर काम करने का स्वतंत्र तरीका प्रदान करने में बहुत पीछे है... इन दिनों... कुछ को छोड़कर... हर दूसरा पत्रकार वही खबर दे रहा है जो सरकार की प्रशंसा करती है... नए चैनल लोगों को सरकार द्वारा की गई गलती से विचलित करने के लिए विभिन्न विषयों पर अनावश्यक बहस दिखाएंगे... इसके कारण, अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो किसी का ध्यान नहीं जाता है... दूसरा कारण यह है कि पत्रकार अपने सिद्धांतों और मूल्यों को खो रहे हैं क्योंकि आज स्थिति ऐसी है कि स्थापना के खिलाफ विषयों पर बोलने या लिखने वाले पत्रकारों को धमकी देना, गाली देना और मारना कई अन्य देशों की तरह भारत में भी एक वास्तविकता बन गई है... देश और दुनिया को झरा दिया है... वहीं, पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमलों की घटनाओं ने एक बार पिर उन्हें सुर्खियों में ला दिया है... जो पत्रकार देश और उसके आम नागरिकों के लिए लिखे वे मरे या प्रताड़ित हुए सरकारी तंत्रों के द्वारा...!

## क्या छापें माननीय मुख्यमंत्री जी ?



कलम  
बंद...

कलम  
बंद...का  
56 वां  
दिन



कलम  
बंद...का  
56 वां  
दिन



कलम  
बंद...

घट्टी-घट्टा के सेही पाठकों, विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...

संपादक : - अविनाश कुमार सिंह

## खुला पत्र

# क्या भ्रष्टाचार का मामला वही होगा दर्ज जहां होगी भाजपा से इतर दल की सरकार ?

- » भ्रष्टाचार की खबरों से दिक्कत... करें? सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार की ओर बढ़ रहे भ्रष्टाचार को उआर करने पत्रकार दौड़ रहा पर पत्रकार की दौड़ के पीछे निर्वाचित जनप्रतिनिधि उसकी दौड़ की गति को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता
- » कमी दिखाओ तो दिक्कत...
- » जनता की परे शानियों को दिखाओ तो दिक्कत...

अम्बिकापुर, 26 अगस्त 2024(घट्टी-घट्टा)। रहे पर पत्रकार ना दिखाएं क्या यही चाहता है जनप्रतिनिधि या फिर सरकारी तंत्र।

# क्या छापें माननीय मुख्यमंत्री जी ?



कलम  
बंद...

कलम  
बंद...का  
56 वां  
दिन



कलम  
बंद...का  
56 वां  
दिन



कलम  
बंद...

घट्टी-घट्टा के स्लेही पाठकों, विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...

संपादक :- अविनाश कुमार सिंह





## तुगलकी फरमान के विरुद्ध कलम बंद अभियान का 56 वां दिन

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के विभाग जनसंपर्क के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री श्री श्यामबिहारी जायसवाल के विभाग के संबंधित समाचारों के प्रकाशन पर जनसंपर्क संचालन के आयुक्त सह संचालक आईपीएस श्री मयंक श्रीवास्तव के मौखिक आदेश पर घटती-घटना के शासकीय विज्ञापन पर रोक लगाकर दबाव बनाने से लोकतंत्र के चौथे स्तर्भ के मूलभूत हक पर कुठाराघात के विरुद्ध कलमबंद अभियान...के पन्द्रहवें दिन भी केंद्र सरकार से अनुमोदित विज्ञापन नियमावली के आदेश को ठेंगा दिखाने वाले जनसंपर्क विभाग के द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं देने के पीछे किसका हाथ...

छत्तीसगढ़ सरकार घर तोड़िए या कार्यालय तोड़िए...इंकलाब होता  
रहेगा इंसाफ तक...

अब तो बताईए मुख्यमंत्री जी...क्या छापें?

क्या छापें स्वास्थ्य मंत्री जी?

क्या छापें आयुक्त सहसंचालक आईपीएस मयंक श्रीवास्तव जी?

क्यूं न लिखें सच?

इमरजेंसी पर बात...हर बात पर आरोप...तो छत्तीसगढ़ में एक आईपीएस व आईएएस के तुगलकी फरमान पर आदिवासी अंचल से विगत 20 वर्षों से प्रकाशित अखबार पर क्यों किया गया जुर्म...?

क्यों कलमबंद आंदोलन के लिए विवश होना पड़ा एक दैनिक अखबार को...?

घटती-घटना के स्थानीय पाठकों, विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...

संपादक :- अविनाश कुमार सिंह